

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी 2022—माघ 29, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 जनवरी 2022

क्रमांक एफ 5-6/2021/एक/1.—राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 22 नवम्बर, 2021 से 3 दिसम्बर, 2021 (12 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पूर्व दिनांक 19 नवम्बर, 2021 से 21 नवम्बर, 2021 तथा अवकाश पश्चात् दिनांक 4 दिसम्बर, 2021 से 5 दिसम्बर, 2021 तक का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 जनवरी 2022

क्रमांक एफ 5-9/2021/एक/1.—राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. सी. एस. सामंत, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 6 दिसम्बर, 2021 से 13 दिसम्बर, 2021 (08 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश तथा अवकाश पूर्व दिनांक 4 दिसम्बर, 2021 से 5 दिसम्बर, 2021 तक का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 दिसम्बर 2021

क्रमांक एफ 20-01/2021/11-6.—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव, राज्य शासन एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-10-2019 के द्वारा लागू राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में निम्नलिखित अनुसार संशोधन करती है।

संशोधन

(एक) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के बिन्दु क्रमांक-10 में प्रावधानित परिशिष्ट-6.10 में वर्णित “अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत” (केवल सूक्ष्म, लघु, मध्यम श्रेणी के उद्योगों/उद्यमों के लिए) के बिन्दु क्रमांक-1 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

“उद्योग विभाग में छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी एवं भू-भाटक की दर 1 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक होगी. संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क, जल शुल्क एवं अन्य कर व उपकर निर्धारित दर पर देय होंगे.

राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में निर्धारित “द” श्रेणी के विकासखण्डों में औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर विभाग में औद्योगिक प्रयोजनार्थ संधारित लैण्ड बैंक/अविकसित भूमि में औद्योगिक पार्कों/क्षेत्रों के लिए चिन्हांकित भूमि को छोड़कर विभागीय लैण्ड बैंक में उपलब्ध अन्य भूमि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की स्थापना हेतु भूमि आबंटन के लिए प्रब्याजि की दर क्षेत्र विशेष के लिए केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईडलाईन दर के 10 प्रतिशत राशि के बराबर होगी. यह निवेश प्रोत्साहन किसी भी हितग्राही को मात्र एक इकाई हेतु अधिकतम 10 एकड़ भूमि के लिए उपलब्ध होगी इस मामले में यह भी आवश्यक होगा कि आवेदित भूमि एकचक्र में विभाग के पास पूर्व से उपलब्ध हो.

(दो) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 16.2 में वर्णित प्रावधान के अनुसरण में नीति के परिशिष्ट-3 में वर्णित प्राथमिकता उद्योगों की सूची में “(अ) वर्गीकरण के आधार पर” के अनुक्रमांक-8 पर स्थित प्रविष्टि में निम्नानुसार संशोधन/परिवर्तन किया जाता है :—

8 विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण तथा सोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण.

(तीन) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 16.2 में वर्णित प्रावधान के अनुसरण में नीति के परिशिष्ट-3 में वर्णित प्राथमिकता उद्योगों की सूची में “(ब) उत्पाद आधारित” में अनुक्रमांक-24 की वर्तमान प्रविष्टि को 25 पर अंतरित करते हुए अनुक्रमांक 24 पर नवीन प्रविष्टि का निम्नांकित अनुसार समावेश किया जाता है :—

24 निजी भूमि पर किये गये वृक्षारोपणों से प्राप्त काष्ठ पर आधारित उद्योग.

25 ऐसे अन्य उत्पादन जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं.

- (चार) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 21 में वर्णित प्रावधान के अनुसरण उद्योग से संबंधित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों के प्रावधान को संशोधित (प्रतिस्थापित) करते हुये, कंडिका क्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका में अनुक्रमांक-24 पर “एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों की सूची” को नवीन परिशिष्ट-6.24 पर समावेश किया जाता है :-

उद्योग से संबंधित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को नीति के परिशिष्ट 6.24 में सूचीबद्ध सेवा गतिविधियों को परिशिष्ट की तालिका के कॉलम-2 दर्शित क्षेत्रों के अनुसार एवं कॉलम-3 में वर्णित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश करने पर इस नीति के प्रावधानों में अन्यथा निर्धारित पात्रतानुसार सामान्य श्रेणी के उद्योगों की भांति औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का लाभ प्रदान किया जावेगा.

उक्त प्रयोजन के लिए एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र जिला व्यापार एवं उद्योगों केन्द्रों द्वारा जारी किये जायेंगे ताकि उन्हें इस नीति में प्रावधानित प्रोत्साहन उपलब्ध हो सके.

परिशिष्ट - 6.24

औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका-21 के अंतर्गत मान्य एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों की सूची

क्र.	सेवा गतिविधि का नाम	न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश की सीमा (राशि रुपये लाख में)
(1)	(2)	(3)
1.	एनएबीएल प्रमाणित औद्योगिक/सामग्री परीक्षण सेवा प्रयोगशाला की स्थापना	15
2.	उद्योग से संबंधित अनुसंधान विकास केन्द्र की स्थापना	100
3.	मशीन संचालित बीज ग्रेडिंग सेवाएं की स्थापना	05
4.	पावर लांड़्रिज की स्थापना	25
5.	सामान्य इंजीनियरिंग एवं फेब्रीकेशन की सेवा इकाई की स्थापना	05
6.	ऑटोमोबाईल रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग सेन्टर सेवा इकाई की स्थापना, केवल “स” एवं “द” श्रेणी के विकासखण्डों में स्थित इकाईयों के लिये	10
7.	ओ.ई.एम. द्वारा मान्यता प्राप्त पहिया संतुलन केन्द्र सेवा इकाई की स्थापना, केवल “स” एवं “द” श्रेणी के विकासखण्डों में स्थित इकाईयों के लिये	05
8.	हॉलमार्क प्रमाणन सेवा केन्द्र की स्थापना	10
9.	श्री डी प्रीटिंग जॉब वर्क इकाई की स्थापना	10
10.	सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं इकाई की स्थापना (IT & IT Enabled Services)	50
11.	हॉस्पिटैलिटी/पर्यटन/एम्प्लुजमेंट पार्क की स्थापना	500
12.	मनोरंजन (एनीमेशन/व्ही.एफ.एक्स, गेमिंग, डबिंग) सेवा केन्द्र की स्थापना	05
13.	Business Process Outsourcing (BPO) सेवा केन्द्र की स्थापना	30
14.	इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग स्टेशन सेवा केन्द्र की स्थापना	10
15.	जिम, व्यायाम शाला सेवा केन्द्र की स्थापना, केवल “स” एवं “द” श्रेणी के विकासखण्डों में स्थापित इकाईयों के लिये	10
16.	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य सेवा गतिविधियां/क्षेत्र	-

- (पांच) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका में अनुक्रमांक-2 पर वर्णित एवं परिशिष्ट-6.2 अंकित तालिका में निम्नलिखित सुधार किया जाता है :—
- (अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए “स” श्रेणी के विकासखंडों में प्राथमिकता श्रेणी के “35” प्रतिशत अनुदान को “40” प्रतिशत अनुदान किया जाता है.
- (ब) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए “स” श्रेणी के विकासखंडों में उच्च प्राथमिकता श्रेणी के “40” प्रतिशत अनुदान को “45” प्रतिशत अनुदान किया जाता है.

तालिका के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे.

- (छः) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 15.26 के पश्चात् नवीन प्रावधान कंडिका क्रमांक 15.27 का निम्नानुसार समावेश किया जाता है :—

(15.27)

- (15.27.1)** ऐसी इकाई जिसने उद्योग स्थापना का कार्य आरंभ किया किंतु, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं कर सकी, यदि ऐसी इकाई द्वारा विभाग से किसी भी प्रकार का आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया गया है तो ऐसी इकाई की परिसंपत्ति को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी द्वारा एन.सी.एल.टी. (National Company Law Tribunal) अथवा सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत क्रय किये जाने पर नवीन क्रेता के द्वारा उद्योग आरंभ किये जाने पर इकाई को “नवीन इकाई” के रूप में अनुदान की पात्रता होगी.

उपरोक्त स्थिति में निवेश की गणना में नवीन क्रेता के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख/अनुबंध में अंकित राशि तथा अनुबंध के निष्पादन दिनांक से उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक तक एवं उत्पादन दिनांक से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों/ सेवा उद्यमों हेतु 6 माह, मध्यम उद्योग/मध्यम सेवा उद्यम हेतु 12 माह, वृहद उद्योगों हेतु 18 माह एवं मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों हेतु 24 माह तक किया गया निवेश मान्य होगा.

- (15.27.2)** ऐसी इकाई जिसने उद्योग स्थापना का कार्य आरंभ किया तथा विभाग से स्टाम्प शुल्क/भू-प्रीमियम में छूट प्राप्त किया गया है किंतु, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं कर सकी, यदि ऐसी इकाई द्वारा विभाग से किसी भी प्रकार का अन्य आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया गया है तो ऐसी इकाई की परिसंपत्ति को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी द्वारा एन.सी.एल.टी. (National Company Law Tribunal) अथवा सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत क्रय किये जाने पर, नवीन क्रेता के पक्ष में पूर्व में लिए गए छूट यथा स्टाम्प शुल्क छूट/भू-प्रीमियम में छूट की अधिसूचना के शर्तों के अधीन शेष अनुदान/छूट/रियायत हेतु पात्रता होगी.

- (15.27.3)** ऐसी इकाई जो वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरांत तथा वर्तमान में उत्पादनरत/बंद है परंतु विभाग से किसी भी प्रकार के अनुदान/छूट/रियायत नहीं लिया गया है. इकाई को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी द्वारा एन.सी.एल.टी. (National Company Law Tribunal) अथवा सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत क्रय किए जाने पर “नवीन इकाई” के रूप में इस नीति के तहत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी. निवेश की गणना में नवीन क्रेता के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख/अनुबंध में अंकित राशि जो बैंक द्वारा प्रमाणित हो मान्य किया जाएगा तथा इकाई में विस्तार/ शक्तीकरण/प्रतिस्थापन किए जाने पर भी नियमानुसार इस नीति के तहत अनुदान, छूट की पात्रता होगी.

- (15.27.4)** ऐसी इकाई जो वाणिज्यिक उत्पादन में आ चुकी है तथा वर्तमान में उत्पादनरत है, साथ ही विभाग से अनुदान/ छूट/रियायत प्राप्त कर चुकी है. ऐसी इकाई को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी को विक्रय करने से पूर्व विभाग से अनुमति लेना आवश्यक होगा. विधिवत् अनुमति पश्चात् इकाई को केवल प्रतिस्थापन/शक्तीकरण/विस्तार की स्थिति में नियमानुसार अनुदान/छूट/रियायत/की पात्रता होगी.

- (15.27.5)** ऐसी इकाई जो पूर्व में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर चुकी हो तथा वर्तमान में बंद हो, साथ ही विभाग से अनुदान/छूट/रियायत प्राप्त कर चुकी हो. ऐसी स्थिति में क्रेता ऐसी इकाई, विभाग द्वारा लागू बंद एवं बीमार उद्योग नीति के तहत अनुदान/छूट/रियायत प्राप्त कर सकती है.

(15.27.6) औद्योगिक नीति 2019-24 के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं सहित जिन सेवा इकाईयों को इस नीति के अंतर्गत आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाना है, ऐसी इकाईयां वाणिज्यिक/औद्योगिक व्यववर्तित भूमि अथवा संबंधित सेवा हेतु व्यववर्तित भूमि पर स्थापित हो सकेंगी.

(सात) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 15.23 में वर्णित प्रावधान के अनुसार निजी औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिये प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित (प्रतिस्थापित) किया जाता है :—

राज्य में निजी औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु न्यूनतम 25 एकड़ भूमि में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत अधिकतम रु. 5 करोड़ का अनुदान तथा स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट एवं भू-पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होंगे.

परंतु, सरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र में उपरोक्त निजी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि उपलब्धता कम होने के कारण 20 एकड़ तक के निजी औद्योगिक क्षेत्रों को भी इन प्रावधानों का लाभ उपलब्ध भूमि के आधार पर अधिकतम अनुदान राशि में समानुपातिक कमी करते हुए प्रकरण स्वीकृत किये जा सकेंगे.

उपरोक्त अनुसार मूल प्रस्तावित क्षेत्रों के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 25 एकड़ भूमि पर अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत अधिकतम रु. 300 लाख तक अनुदान तथा स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट एवं भू-पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होंगे.

(आठ) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत समय-समय पर विभिन्न विषयों पर किये गये संशोधन दिनांक 01 नवंबर, 2019 से लागू मान्य किये जाते हैं :—

क्र. (1)	अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक (2)	विषय का संक्षिप्त विवरण (3)
1.	एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 01 जून 2020,	धान आधारित बायो जैव ईंधन/एथनॉल इकाईयों को पात्रता के संबंध में प्रावधान का समावेश हेतु संशोधन.
2.	एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 30 जुलाई 2020,	धान आधारित बायो जैव ईंधन/एथनॉल इकाईयों को सहकारी क्षेत्र के साथ पीपीपी मोड में स्थापना पर पात्रता के संबंध में प्रावधान का समावेश हेतु संशोधन.
3.	एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 14 सितम्बर 2020,	धान आधारित बायो जैव ईंधन/एथनॉल इकाईयों को अर्ली बर्ड इन्सैंटिव हेतु 06 माह के स्थान पर 18 की अवधि के प्रावधान हेतु संशोधन.
4.	एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर 2020,	स्टार्टअप पैकेज, अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग पैकेज, स्थाई पूंजी निवेश अनुदान आदि का प्रावधान समावेश एवं अन्य संशोधन.
5.	एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 04 नवम्बर 2020,	वनांचल उद्योग पैकेज का समावेश एवं अन्य संशोधन.

(नौ) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक 16.2 में वर्णित प्रावधान के अनुसरण में परिशिष्ट-2 में वर्णित उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची में अनुक्रमांक-17 की वर्तमान प्रविष्टि को अनुक्रमांक-18 पर अंतरित करते हुए अनुक्रमांक 17 पर नवीन प्रविष्टि निम्नांकित अनुसार समावेश की जाती है :—

17. धान/चावल उपार्जन में प्रयुक्त होने योग्य जूट बैग/बारदाना निर्माण उद्योग.

18. ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जावें.

उपरोक्त (एक) से (नौ) तक के संशोधन औद्योगिक नीति 2019-24 में दिनांक 01 नवम्बर, 2019 से लागू माने जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 दिसम्बर 2021

क्रमांक एफ 1-16/2004/11/6 (पार्ट).—भारतीय भागीदारी अधिनियम-1932 (1932 का नंबर-9) की धारा-57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट निरीक्षक, फर्म्स एवं संस्थाएँ को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए फार्मों के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करती है तथा वे उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम/पद (2)	अधिकारिता (3)	राजस्व संभाग (4)
1.	श्री प्रमोद कुजूर, निरीक्षक फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ (प्रभारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार)	दुर्ग संभाग	दुर्ग संभाग
2.	श्रीमती अनुपमा कुजूर निरीक्षक फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ (प्रभारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार)	बस्तर संभाग	बस्तर संभाग
3.	श्री सतीश कुमार शर्मा निरीक्षक फर्म्स एवं संस्थाएँ, बिलासपुर संभाग बिलासपुर (प्रभारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार)	सरगुजा संभाग	सरगुजा संभाग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलेश बंसोड़, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 18 नवम्बर 2021

रा.प्र.क्रमांक/01/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	गोरियापीपर	1.921	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.).	पुटा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 नवम्बर 2021

रा.प्र.क्रमांक/02/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	कुसू	5.229	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्र-1, अम्बिकापुर.	पुटा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 01/अ-82/2021-22.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	दरिमा	पोंडिपा प.ह.नं. 29	0.696	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.).	घुनघुट्टा श्याम परि- योजना के डूब हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 23 दिसम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202009042100037/अ-82/2020-21.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सकरबोगा प.ह.नं. 12	0.225	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायगढ़ संभाग जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	सकरबोगा से उड़िसा सीमा मार्ग लं. 2.30 कि.मी. निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 दिसम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202009042100038/अ-82/2020-21.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोसमपाली प.ह.नं. 40	0.259	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायगढ़ संभाग जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	सकरबोगा से उड़िसा सीमा मार्ग लं. 2.30 कि.मी. निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 25 जनवरी 2022

क्रमांक 06//अ-82/2016-17.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	सुरता प.ह.नं. 33	2.220	प्राधिकृत अधिकारी, सरगुजा रेल कॉरीडोर प्रा.लि.	रेलवे लाइन का निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 25 जनवरी 2022

क्रमांक 09/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	सलका प.ह.नं. 11	0.350	प्राधिकृत अधिकारी, सरगुजा रेल कॉरीडोर प्रा.लि.	रेलवे लाइन का निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 जनवरी 2022

प्र. क्रमांक/78/भू-अर्जन/12/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	
(क)	जिला-राजनांदगांव
(ख)	तहसील-अंबागढ़ चौकी
(ग)	नगर/ग्राम-बिहरीखुर्द
(घ)	लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
325	0.020
योग	01 0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मोंगरा परियोजना के अंतर्गत डूबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 जनवरी 2022

प्र. क्रमांक/79/भू-अर्जन/11/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-घोरदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.263 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
54/4	0.081
54/8	0.101
48/4	0.081
योग	03 0.263

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मोंगरा परियोजना के अंतर्गत डूबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तारन प्रकाश सिन्हा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 9 दिसम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/1821/18/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.531 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
605/1द	0.144
613	0.032
615	0.040
616	0.082
627	0.128
629	0.040
623	0.030
697	0.028
622	0.090
624	0.239
625	0.375
698	0.032
699/1	0.070
580	0.082
579	0.080
581	0.036
योग	16 1.531

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ साजादरहा व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 दिसम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/1822/19/अ-82/2017-18.—
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-धरमजयगढ़
(ग) नगर/ग्राम-जमाबीरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.173 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108	0.044
92	0.049
97	0.024
245/9	0.040
245/10	0.016
245/11	0.004
247	0.243
287	0.247
286	0.004
312/1	0.057
313	0.073
314	0.332
योग	12
	1.173

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ जमाबीरा व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 2 नवम्बर 2021

क्रमांक 07/अ-82/2020-21.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-लुण्ड्रा
(ग) नगर/ग्राम-चलगली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.033 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
269/16	0.033
योग	0.033

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गगोली व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2022

फा.क्रमांक-18/03/निर्वाचन याचिका/2018-22/396.— भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 82/छ.ग.-वि.स./((03/2019))/2022/3300 दिनांक 27 जनवरी 2022 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा निर्वाचन अर्जी संख्या-03/2019 में दिए गए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के तारीख दिनांक 06 जुलाई, 2021 के आदेश को राज्य के शासकीय राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है।

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 27 जनवरी, 2022—07 माघ, 1943 (शक)

सं. 82/छ.ग.-वि.स./((03/2019))/2022.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 (ख) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा निर्वाचन अर्जी सं. 03/2019 में दिये गये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के तारीख 06 जुलाई, 2021 के आदेश को प्रकाशित करता है।

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Election Petition No. 3 of 2019

Election Petitioner : Hira Singh Markam, S/o Late Dev Sai Markam, Aged about 78 years, R/o Village Tivarta, Post Tivarta, Tahsil Pali, Police Station Pali, District-Korba (C.G.).

VERSUS

Election Respondents :

1. Mohit Ram Kerketta, S/o Late Budhram Kerketta, Aged about 52 years, (Elected Candidate), R/o Village Komli, Post Silli, Tahsil Pali, PS Pali, District Korba (C.G.).
2. Uike Ramdyaal, S/o Kunjal Singh Uike, Aged about 53 years, R/o Village Bokramuda, H. No. 84, Village Panchayat Bagra, Tahsil Pendra Road, District Bilaspur (C.G.)
3. Sukhnandan Singh Puhup, House No. 322, Chhapartola, Jalke, Tahsil Pondi-Uparoda, District Korba (C.G.) Pin No. 495445.
4. Cresentia Kujur, R/o AB 1079-80, Block 3, Yamuna Vihar, Jamuni Pali, Tahsil Katghora, District Korba (C.G.).
5. Tapeswar Singh Maravi, R/o Village Sakola, Post Kotmikala, Tahsil Pendra, District Bilaspur (C.G.).
6. Alwan Singh, R/o Darrabhata, Block Pondi-Uparoda, District Korba (C.G.).

7. Dr. L. S. Uday Singh, R/o Village Sasin, Post Jatga, Tahsil Pondi-Uparoda, District Korba (C.G.).
8. The Election Commission of India, through the Chief Election Commissioner, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi.
9. Chief Electoral Officer/Commissioner of State Election Commission, Chhattisgarh, Shashtri Chowk, Old Mantralaya, Raipur (C.G.).
10. Electoral Registration Officer, Raipur, Shashtri Chowk, Old Mantralaya, Raipur (C.G.).
11. The District Electoral Officer, Korba, District Korba (C.G.).
12. The Returning Officer, Legislative Region No. 23, Pali Tanakhar Legislative Assembly, District Korba (C.G.).

For Respondents No. 1 and 5 to 12 :- None present

Hon'ble Shri Justice Sanjay K. Agrawal

Order On Board

06-07-2021

1. Proceedings of this matter have been taken-up through video conferencing.
2. On 7-6-2021, it was informed to this Court that the Sole election petitioner has died and pursuant to that, this Court by order dated 7-6-2021, directed for publication of notice as required under Section 112(2) of the Representation of the People Act, 1951 read with Rule 311 of the High Court of Chhattisgarh Rules, 2007. It has now been reported that the fact of death of election petitioner Hira Singh Markam has already been published in the Chhattisgarh Rajpatra on 15th June, 2021 and no one has applied for substitution as election petitioner within 14 days of such publication and therefore no question of substitution arises to continue the proceeding.
3. In view of the aforesaid, the election petition is declared as abated on the death of the sole election petitioner in terms of Section 112(1) of the Representation of the People Act, 1951. Accordingly, the election petition is closed. No order as to cost(s).

Sd/-

(Sanjay K. Agrawal)
Election Judge.

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 27th January, 2022—07th Magha, 1943 (Saka)

No. 82/CGH-LA/(03/2019)/2022.—In pursuance of Section 106 (b) of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby publish Order dated the 06th July, 2021 of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, in Election Petition No. 03 of 2019.

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Election Petition No. 3 of 2019

Election Petitioner : Hira Singh Markam, S/o Late Dev Sai Markam, Aged about 78 years, R/o Village Tivarta, Post Tivarta, Tahsil Pali, Police Station Pali, District-Korba (C.G.).

VERSUS

Election Respondents :

1. Mohit Ram Kerketta, S/o Late Budhram Kerketta, Aged about 52 years, (Elected Candidate), R/o Village Komli, Post Silli, Tahsil Pali, PS Pali, District Korba (C.G.).
2. Uike Ramdya, S/o Kunjal Singh Uike, Aged about 53 years, R/o Village Bokramuda, H. No. 84, Village Panchayat Bagra, Tahsil Pendra Road, District Bilaspur (C.G.)
3. Sukhnandan Singh Puhup, House No. 322, Chhapartola, Jalke, Tahsil Pondi-Uparoda, District Korba (C.G.) Pin No. 495445.
4. Cresentia Kujur, R/o AB 1079-80, Block 3, Yamuna Vihar, Jamuni Pali, Tahsil Katghora, District Korba (C.G.).
5. Tapeswar Singh Maravi, R/o Village Sakola, Post Kotmikala, Tahsil Pendra, District Bilaspur (C.G.).
6. Alwan Singh, R/o Darrabhata, Block Pondi-Uparoda, District Korba (C.G.).
7. Dr. L. S. Uday Singh, R/o Village Sasin, Post Jatga, Tahsil Pondi-Uparoda, District Korba (C.G.).
8. The Election Commission of India, through the Chief Election Commissioner, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi.
9. Chief Electoral Officer/Commissioner of State Election Commission, Chhattisgarh, Shashtri Chowk, Old Mantralaya, Raipur (C.G.).
10. Electoral Registration Officer, Raipur, Shashtri Chowk, Old Mantralaya, Raipur (C.G.).
11. The District Electoral Officer, Korba, District Korba (C.G.).
12. The Returning Officer, Legislative Region No. 23, Pali Tanakhar Legislative Assembly, District Korba (C.G.).

For Respondents No. 1 and 5 to 12 :-

None present

Hon'ble Shri Justice Sanjay K. Agrawal**Order On Board****06-07-2021**

1. Proceedings of this matter have been taken-up through video conferencing.
2. On 7-6-2021, it was informed to this Court that the Sole election petitioner has died and pursuant to that, this Court by order dated 7-6-2021, directed for publication of notice as required under Section 112(2) of the Representation of the People Act, 1951 read with Rule 311 of the High Court of Chhattisgarh Rules, 2007. It has now been reported that the fact of death of election petitioner Hira Singh Markam has already been published in the Chhattisgarh Rajpatra on 15th June, 2021 and no one has applied for substitution as election petitioner within 14 days of such publication and therefore no question of substitution arises to continue the proceeding.
3. In view of the aforesaid, the election petition is declared as abated on the death of the sole election petitioner in terms of Section 112(1) of the Representation of the People Act, 1951. Accordingly, the election petition is closed. No order as to cost(s).

Sd/-

(Sanjay K. Agrawal)
Election Judge.

By order,

Sd/-

(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.**संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़****कृषि विकास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)**

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2021

क्रमांक गन्ना/क्षेत्र आरक्षण/2021-22/121.—मैं यशवन्त कुमार, गन्ना आयुक्त छ.ग. रायपुर, दंतेश्वरी मैया, सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला बालोद के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित गन्ना क्षेत्र को, निम्नानुसार क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 के लिये आरक्षित घोषित करता हूँ. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्नानुसार केन्द्रों पर शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्र.	क्रय केन्द्र	जिला	वि.ख.	ग्रामों की संख्या	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कारखाना द्वार	बालोद	बालोद	45	176.19
			डौडी	23	38.04
			गुरुर	64	114.04
			डौडी लोहारा	27	72.93
			गुण्डरदेही	44	143.19

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		दुर्ग	दुर्ग	3	6.40
			पाटन	4	2.80
			धमधा	1	11.00
		राजनांदगांव	राजनांदगांव	2	7.60
			खैरागढ़	1	10.00
			मानपुर	4	7.00
			छुरिया	4	3.22
		धमतरी	कुरुद्ध	1	0.22
			धमतरी	4	3.22
		कांकेर	चारामा	8	16.69
		बेमेतरा	बेमेतरा	3	30.00
			बेरला	11	140.00
			योग	246	782.32

यशवन्त कुमार,
गन्ना आयुक्त.

पेराई सत्र 2021-22 के लिये विकासखंडवार आरक्षित किए जाने वाले ग्रामों और उसमें गन्ना क्षेत्र
उपलब्धता एवं औसत उत्पादन की जानकारी

क्रमांक	जिला	विकासखंड का नाम	कृषक संख्या	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों की संख्या	आरक्षित रकबा हेक्टेयर में	औसत उत्पादन (टन में)
1	बालोद	बालोद	200	45	176.19	10571
2	बालोद	डौडी	40	23	38.04	2282
3	बालोद	गुरुर	179	64	114.04	6842
4	बालोद	डौण्डीलोहारा	64	27	72.93	4376
5	बालोद	गुण्डरदेही	148	44	143.19	8591
6	दुर्ग	दुर्ग	4	3	6.40	384
7	दुर्ग	पाटन	4	4	2.80	168
8	दुर्ग	धमधा	1	1	11.00	660
9	राजनांदगांव	राजनांदगांव	3	2	7.60	456
10	राजनांदगांव	खैरागढ़	1	1	10.00	600
11	राजनांदगांव	मानपुर	7	4	7.00	420
12	राजनांदगांव	छुरिया	3	1	3.00	180
13	धमतरी	धमतरी	4	4	3.22	193
14	धमतरी	कुरुद्ध	1	1	0.22	13
15	कांकेर	चारामा	16	8	16.69	1001
16	बेमेतरा	बेमेतरा	26	3	30.00	1800
17	बेमेतरा	बेरला	23	11	140.00	8400
महायोग:-			724	246	782.32	46939

पेराई सत्र 2021-22 के लिये जिलावार/विकासखंडवार आरक्षित किए जाने वाले ग्रामों की सूची

क्र.	जिला/वि.ख. /ग्राम	कृषक संख्या	पुराना रकबा (हे में)	नया रकबा (हे में)	कुल रकबा (हे में)	अनुमानित औसत उत्पादन (टन में)
1.	बालोद	631	290.94	253.45	544.39	32663
1.	बालोद	200	117.29	58.9	176.19	10571
1	धुमका	1	1	0	1	60
2	खपरी	1	0.4	0	0.4	24
3	झलमला	1	2.2	0	2.2	132
4	बघमरा	2	1.4	0.3	1.7	102
5	बी. जामगांव	1	0.4	0.24	0.64	38
6	बरही	3	0.3	0.54	0.84	50
7	बोड़की	1	1	0	1	60
8	बालोद	4	4.2	0	4.2	252
9	बेलमाण्ड	1	0.5	0	0.5	30
10	करकाभाट	1	0	0.57	0.57	34
11	करहीभदर	14	4.86	3.04	7.9	474
12	काड़े	1	0	0.24	0.24	14
13	कोंहगाटोला	1	1	0	1	60
14	कन्नेवाड़ा	2	1	1.7	2.7	162
15	मटिया	3	4.8	0.06	4.86	292
16	मुजगहन	9	4.23	1.18	5.41	325
17	मुल्ले	1	1.2	0	1.2	72
18	बिरेतरा	5	3.2	0.96	4.16	250
19	पिपरछेड़ी	12	4.27	6	10.27	616
20	घिरईगोड़ी	10	3.67	0.86	4.53	272
21	निपानी	7	6.2	1.86	8.06	484
22	लिमोरा	1	0.36	0.24	0.6	36
23	हीरापुर	11	5.98	2.1	8.08	485
24	हराठेमा	1	0.6	0	0.6	36
25	भोईनापार	1	0.8	0	0.8	48
26	भे.नवागांव	8	4.17	4.7	8.87	532
27	परसोदा ज	1	0.6	0	0.6	36
28	पोण्डी	1	0	1.2	1.2	72
29	सांकरा क	8	6.42	0.62	7.04	422
30	सौंहतरा	10	8.03	6.64	14.67	880
31	सुन्दरा	3	7.6	0.2	7.8	468
32	डेंगरापार	1	0.4	0	0.4	24
33	दरीटोला	4	1.53	0.88	2.41	145

34	चारवाही	20	5.39	12.46	17.85	1071
35	तमोरा	10	3.48	2.77	6.25	375
36	तरौद	2	0.4	0.4	0.8	48
37	जमरूवा	4	2.29	0.21	2.5	150
38	जुंगेरा	2	1.8	0.7	2.5	150
39	नर्रा	1	0	1.2	1.2	72
40	नागाडबरी	15	16.74	3.21	19.95	1197
41	अमोरा	7	1.95	1.32	3.27	196
42	अरौद	1	0	0.04	0.04	2
43	ओरमा	1	0	1.1	1.1	66
44	गोडरी	1	0	0.16	0.16	10
45	लाटाबोड़	5	2.92	1.2	4.12	247
2	डौण्डी	40	17.98	20.06	38.04	2282
1	धोबेदंड	1	0.2	0.2	0.4	24
2	घोटिया	1	0.5	0	0.5	30
3	खुर्सीटिकुर	1	1.12	0	1.12	67
4	खैरवाही	1	0	1.2	1.2	72
5	ठेमा बुर्जुग	1	0.5	0	0.5	30
6	बोरिद	1	0.8	0.2	1	60
7	बेलोदा	4	4.48	3.33	7.81	469
8	कोटागांव	1	0	0.2	0.2	12
9	कुरुभाट	1	0	0.33	0.33	20
10	कुरुमकसा	1	0.4	0.4	0.8	48
11	मंगलतराई	6	2.88	2.9	5.78	347
12	बिटाल	1	0	0.2	0.2	12
13	सिंघोला	2	0.6	1.4	2	120
14	गिधाली	2	1.2	1.3	2.5	150
15	भरौटोला	1	0	0.6	0.6	36
16	पेंझी	3	1.6	1.4	3	180
17	साल्हे	4	1	2.3	3.3	198
18	डौण्डी	2	1	0.2	1.2	72
19	दीघवाडी	1	0.9	0	0.9	54
20	फगुनदाह	2	0.8	1.4	2.2	132
21	आमाबाहरा	1	0	1.2	1.2	72
22	आवराटोला	1	0	1	1	60
23	गुण्डराटोला	1	0	0.3	0.3	18
3	डौण्डी लोहारा	64	36.29	36.64	72.93	4376
1	खेरथा	2	0.8	2	2.8	168
2	खैरीडीह	3	1	1.4	2.4	144
3	खैरा	2	1.31	0.51	1.82	109
4	झींकाटोला	1	0	1	1	60
5	बडा जुंगेरा	1	0	0.6	0.6	36
6	बुल्लुटोला	1	0	1	1	60

7	बुल्लूटोला	1	0.6	0.4	1	60
8	ब.जुगेरा	1	0	0.6	0.6	36
9	कापसी	1	0.5	0	0.5	30
10	कुंआगांव	1	1	0	1	60
11	महराजपुर	1	1.6	0.4	2	120
12	माटरी	3	0	2.38	2.38	143
13	माटरी/के.जुगेरा	1	3	2	5	300
14	चिल्हाटीकला	10	4.7	8.25	12.95	777
15	होदेकसा	1	0	2	2	120
16	भीमकन्हार	1	1	0	1	60
17	परसुली	1	0.13	0	0.13	8
18	रानीतराई	1	0	1	1	60
19	रेंघई	3	2	2.2	4.2	252
20	रेंघनी	18	12.85	7	19.85	1191
21	संबलपुर	1	0.6	0.2	0.8	48
22	सोरली	1	1	0.3	1.3	78
23	सेम्हरडीह	1	0.8	0	0.8	48
24	नारगी	1	0.8	0.8	1.6	96
25	ग. नवागांव	2	2	1.4	3.4	204
26	ग.नवागांव	2	0	0.8	0.8	48
27	लोहारा	2	0.6	0.4	1	60
4	गुण्डरदेही	148	55.92	87.27	143.19	8591
1	धनगांव	2	2.4	0.4	2.8	168
2	खपरी	1	0	0.42	0.42	25
3	खपरी (ब)	1	0.3	0	0.3	18
4	खपरी ब	1	0	0.6	0.6	36
5	खैरबना	2	0	6	6	360
6	ईरागुड़ा	1	2	0.4	2.4	144
7	बघेली	1	0.25	0	0.25	15
8	बरबसपुर	2	1.2	0.3	1.5	90
9	बोरगहन	2	0	1.1	1.1	66
10	बोदल *	5	1.5	4	5.5	330
11	बेलौदी	3	1.42	0	1.42	85
12	कमरौद	2	0	4	4	240
13	कांदुल	1	0.4	0.8	1.2	72
14	कोड़ेवा	1	1.2	0	1.2	72
15	कुरदी	3	0	7.5	7.5	450
16	कलंगपुर	2	0.6	1.5	2.1	126
17	मोखा	4	0.4	3.7	4.1	246
18	मोंगरी	1	1.6	0	1.6	96
19	भिलाई	1	0.05	0	0.05	3
20	पिनकापार	3	1	1.58	2.58	155
21	सियनमरा	1	0.44	0	0.44	26

22	सिराभाठा	1	0.3	0	0.3	18
23	चिचबोड़	7	3.86	0.8	4.66	280
24	टिकरी	1	3.5	0	3.5	210
25	भोधीपार	14	4	5.47	9.47	568
26	परसवानी	1	0	0.3	0.3	18
27	परसतराई	2	0.5	0.76	1.26	76
28	पसौद	2	0	2	2	120
29	पेण्डी	5	0.7	1.6	2.3	138
30	पेंडी	32	10.6	21.34	31.94	1916
31	पैरी	3	0.2	2.22	2.42	145
32	रजोली	1	0	0.3	0.3	18
33	सरेखा	1	1	0.6	1.6	96
34	सांकरी	2	0	2.5	2.5	150
35	सलोनी	3	1.3	1.1	2.4	144
36	देवगहन	1	3.5	0	3.5	210
37	चंदनबिरही	1	0	1	1	60
38	चाराघार	1	0.4	0.42	0.82	49
39	फुण्डा	14	4.4	6.62	11.02	661
40	जोरातराई	5	0.8	5.34	6.14	368
41	जेवरतला	1	0.2	0.5	0.7	42
42	अचौद	7	2.9	1.4	4.3	258
43	अर्जुन्दा	1	1	0	1	60
44	गोरकापार	2	2	0.7	2.7	162
5	गुरुर	179	63.46	50.58	114.04	6842
1	धोबनपुरी	1	0.22	0	0.22	13
2	धनेली	3	2.9	1.04	3.94	236
3	रुपुटोला	4	0.8	1	1.8	108
4	धोबनपुरी	1	0.2	0	0.2	12
5	रुपुटोला	1	0.4	0	0.4	24
6	घोघोपुरी	8	5.41	0	5.41	325
7	खर्रा	3	1.8	1.1	2.9	174
8	खुंदनी	2	0	1	1	60
9	खुन्दनी	1	0.1	0.1	0.2	12
10	खैरीडीगी	2	0.2	1.9	2.1	126
11	ठेकवाडीह	13	7.51	1.1	8.61	517
12	बोरतरा	1	0.2	0	0.2	12
13	बोड़रा	4	0.2	1.25	1.45	87
14	बालोदगहन	1	1.2	0	1.2	72
15	बगदई	1	0.5	0	0.5	30
16	कंकालीन	1	0.2	0	0.2	12
17	कंवर	1	1.2	0.4	1.6	96
18	करियाटोला	3	1	1.52	2.52	151
19	कपरमेटा	6	1.3	4.6	5.9	354

20	करैझर	2	0	2.7	2.7	162
21	कोसागोंदी	1	0	0.5	0.5	30
22	कोचेरा	1	0	0.5	0.5	30
23	कुम्हारखान	1	0.7	0	0.7	42
24	कन्हारपुरी	3	0	1.5	1.5	90
25	मंगचुवा	3	1.2	0.55	1.75	105
26	मरकाटोला	3	1	1.9	2.9	174
27	मोखा	1	0	1	1	60
28	मुड़पार	1	0	0.5	0.5	30
29	मुजालगोंदी	5	1.7	0	1.7	102
30	मुजगहन	4	0.8	1	1.8	108
31	हितेकसा	23	4.05	4.8	8.85	531
32	चिरचारी	2	2.22	0	2.22	133
33	भोधली	5	1.55	1	2.55	153
34	भानपुरी	2	1.02	0	1.02	61
35	भेजा जंगली	1	0.2	0	0.2	12
36	पेण्डरवानी	3	1.4	1.14	2.54	152
37	पेंवरो	1	0	0.15	0.15	9
38	पेरपार	1	1.2	0.4	1.6	96
39	पलारी	1	0	0.8	0.8	48
40	रमतारा	5	2.9	0	2.9	174
41	सांगली	1	0	1.72	1.72	103
42	सोरर	4	1.64	0.25	1.89	113
43	सो.डों.	4	0.8	2	2.8	168
44	सुर्रा	1	0.4	0	0.4	24
45	ढकारी	5	0	4.5	4.5	270
46	दुपचेरा	2	1.4	0	1.4	84
47	छेड़िया	3	1.17	0	1.17	70
48	देवकोट	1	0	0.5	0.5	30
49	चुल्हापथरा	7	2.33	1.56	3.89	233
50	तार्री	1	0.72	0	0.72	43
51	जगतार	3	0.1	0.9	1	60
52	नंगझर	1	0.8	0.4	1.2	72
53	नांहदा	1	0	0.5	0.5	30
54	नारागांव	2	0.6	2	2.6	156
55	नवागांव	1	0	0.1	0.1	6
56	नैकुरा	1	0.8	0	0.8	48
57	नगबेलडीह	2	0.2	0.3	0.5	30
58	अकलघारा	2	1.2	0.5	1.7	102
59	अरमरीकला	1	0.81	0	0.81	49
60	आमापानी	1	0	0.7	0.7	42
61	ओड़ेनाडीह	2	0.8	0	0.8	48
62	टे.बरपारा	3	0.5	0.8	1.3	78

63	अर्जुनी	2	2.31	0	2.31	139
64	गुरुर	2	1.6	0.4	2	120
2	कांकेर	16	4.7	11.99	16.69	1001
1	चारामा	16	4.7	11.99	16.69	1001
1	खैरवाही	7	0	8	8	480
2	कण्डेल	1	0.07	0	0.07	4
3	कोटतरा	1	1.93	0	1.93	116
4	हाराडुला	1	0.17	0	0.17	10
5	परसोदा	1	0.8	0	0.8	48
6	साल्हेटोला	1	0.4	0.64	1.04	62
7	बुचरुंगपुर	3	1.33	2.39	3.72	223
8	आंवरी	1	0	0.96	0.96	58
3	राजनांदगांव	14	7	20.6	27.6	1656
1	खैरागढ़	1	7	3	10	600
1	जोरातराई	1	7	3	10	600
2	मानपुर	7	0	7	7	420
1	घोटिया	1	0	1	1	60
2	खरदी	1	0	1	1	60
3	बाको	2	0	2	2	120
4	संबलपुर	3	0	3	3	180
3	राजनांदगांव	3	0	7.6	7.6	456
1	खैरा	2	0	7	7	420
2	दिवानभेंडी	1	0	0.6	0.6	36
4	छुरिया	3	0	3	3	180
1	शिकारीमाहका	3	0	3	3	180
4	दुर्ग	9	14.4	5.8	20.2	1212
1	धमधा	1	11	0	11	660
1	राखीजोबा	1	11	0	11	660
2	पाटन	4	0	2.8	2.8	168
1	मर्ला	1	0	1	1	60
2	मुड़पार	1	0	1	1	60
3	पौहा	1	0	0.4	0.4	24
4	गुड़ियारी	1	0	0.4	0.4	24
3	दुर्ग	4	3.4	3	6.4	384
1	खम्हरिया	2	0	2	2	120
2	कोड़िया	1	0	1	1	60
3	अण्डा	1	3.4	0	3.4	204
5	धमतरी	5	2.44	1	3.44	206
1	धमतरी	4	2.22	1	3.22	193
1	कसावही	1	0	1	1	60
2	मड़वापथरा	1	0.8	0	0.8	48
3	डीमरटीकुर	1	1.02	0	1.02	61
4	आमदी	1	0.4	0	0.4	24

2	कुरुद	1	0.22	0	0.22	13
1	गाड़ाडीह	1	0.22	0	0.22	13
6	बेमेतरा	49	167.5	2.5	170	10200
1	बेरला	23	137.5	2.5	140	8400
1	बेरला	5	26	0	26	1560
2	गिरहोला	1	2	0	2	120
3	परपोड़ा	2	9.5	2.5	12	720
4	सोंढ	1	24	0	24	1440
5	बहेरा	2	10	0	10	600
6	आनंदगांव	2	9	0	9	540
7	नयागांव	2	11	0	11	660
8	कोदवा	2	8	0	8	480
9	देवतर	2	13	0	13	780
10	चोरभट्टी	2	14	0	14	840
11	सोरीभाठा	2	11	0	11	660
2	बेमेतरा	26	30	0	30	1800
1	बेमेतरा	12	15	0	15	900
2	खण्डसरा	7	7	0	7	420
3	चंदनु	7	8	0	8	480
Grand Total		724	486.98	295.34	782.32	46939

जिलो की संख्या-06, विकासखण्डों की संख्या-17, ग्रामों की संख्या-246

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 20th December 2021

No. 12918/Rules/2021.—In exercise of the powers conferred under Articles 225 and 227 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh is pleased to make the following further amendments in the High Court of Chhattisgarh Rules, 2007, which shall come into force with immediate effect :—

AMENDMENTS

1. The following be added at the end of existing Rule 41 of the High Court of Chhattisgarh Rules, 2007 :—

“except Writ Appeal.”

2. The following be added at Sr. No. 27 after Sr. No. 26 of the Rule 140 of the High Court of Chhattisgarh Rules, 2007 with full name-Civil Reference :—

“(27) **CVLREF** : Civil Reference Under Section 113 R/w order XLVI Rule 1 of CPC and under any other Central and State Law”

By order of Hon’ble the High Court,
SANJAY KUMAR JAISWAL, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

क्रमांक 338/दो-2-29/2007.—श्री सुरेश कुमार सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव को उनके आवेदन पत्र दिनांक 10-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

क्रमांक 339/दो-3-46/2007.—श्रीमती किरण चतुर्वेदी, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर-चांपा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 23-10-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

क्रमांक 340/दो-2-21/2015.—श्री नरेन्द्र सिंह चावला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग, को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

क्रमांक 341/दो-3-14/2003.—श्री राकेश बिहारी घोरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा (अंबिकापुर) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 12-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

क्रमांक 342/दो-3-29/2012.—श्रीमती सुषमा सावंत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-12-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

क्रमांक 343/दो-3-2/2006.—श्री अरविन्द कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 15-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

क्रमांक 344/दो-3-25/2007.—श्री मंसूर अहमद, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), राजनांदगांव को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

क्रमांक 345/दो-3-7/2015.—श्री संतोष शर्मा, रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30-10-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

क्रमांक 346/दो-3-34/2008.—श्री संजय कुमार जायसवाल, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 09-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 248/दो-2-17/2015.—श्री बलराम प्रसाद वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 17-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 349/दो-2-4/2009.—श्री अशोक कुमार साहू, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बस्तर स्थान जगदलपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 350/दो-3-26/2014.—श्री सिराजुद्दीन कुरैशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03-12-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 351/दो-2-14/2015.—श्री सुधीर कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी को उनके आवेदन पत्र दिनांक 05-10-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 352/दो-2-37/2019.—श्रीमती सुमन एक्का, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27-10-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 353/दो-3-18/2007.—श्री डॉक्टर लाल कटकवार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 08-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 354/दो-2-4/2004.—श्री विनय कुमार कश्यप, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव को उनके आवेदन पत्र दिनांक 17-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 355/दो-2-20/2019.—श्री थॉमस एक्का, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सरगुजा (अंबिकापुर) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 28-10-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 356/दो-3-27/2007.—श्रीमती नीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 10-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 357/दो-3-13/2008.—श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-12-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 358/दो-3-30/2008.—श्री मो. रिजवान खान, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 359/दो-3-32/2007.—श्री देवेन्द्र नाथ भगत, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), सरगुजा (अंबिकापुर) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 12-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 360/दो-3-28/2009.—श्री संतोष कुमार आदित्य, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 10-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 361/दो-3-65/2007.—श्री जगदम्बा राय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 362/दो-3-35/2007.—श्री रमार्शकर प्रसाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 363/दो-2-30/2016.—श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 11-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 364/दो-11-4/2011.—श्रीमती अनिता डहरिया, तत्कालीन न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेमेतरा वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 17-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 365/दो-11-4/2011.—श्रीमती अनिता डहरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 17-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 366/दो-3-2/2009.—श्री जयदीप विजय निमोणकर, तत्कालीन न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कवर्धा वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-10-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 367/दो-3-2/2009.—श्री जयदीप विजय निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-11-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 368/दो-3-36/2011.—श्री अशोक कुमार लूनिया, तत्कालीन न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बालोद वर्तमान सेवानिवृत्त को उनके आवेदन पत्र दिनांक 24-09-2021 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्रमांक 369/दो-3-36/2011.—श्री अशोक कुमार लूनिया, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बालोद दिनांक 31-10-2021 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,

आर. पी. देवांगन,
बजट अधिकारी.
